भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4029

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

विजयनगरम के लिए एआई, प्रौद्योगिकी और रोजगार पहलें

4029. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'इंडिया एआई मिशन' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाओं सहित आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही या प्रस्तावित किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) या प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विजयनगरम के लिए कोई एआई नवाचार केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, प्रौद्योगिकी पार्क, इन्क्यूबेशन केंद्र या डिजिटल कौशल केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है या विचाराधीन है;
(ग) सरकार द्वारा विजयनगरम के युवाओं को एआई, कोडिंग और डिजिटल कौशलों से लैस करने तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार के नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी और एआई-संबद्ध पहलों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए विजयनगरम में सृजित होने की उम्मीद वाले रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का विशाखापट्टनम के बढ़ते आईटी/प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र और बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर विजयनगरम जिले तक प्रौद्योगिकी-संबद्ध रोजगार लाभों का विस्तार करने का विचार है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ड़):** भारत की एआई नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य एआई से जुड़े जोखिमों का समाधान करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार सृजित करना है।

भारत की एआई रणनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख सुदृढ़ कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है।

<u>आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार:</u>

सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की दिशा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करती है, जो निम्नानुसार है:

<u>इंडियाएआई मिशन</u>

इंडियाएआई मिशन में सात स्तंभ हैं जिनमें एआई मॉडल का विकास, अनुप्रयोग, डेटासेट, प्रतिभा विकास और किफ़ायती गणना शामिल है।

इंडियाएआई लैब्स:

- 27 इंडिया डेटा और एआई लैब्स की स्थापना की गई, जो 3,500 से अधिक छात्रों के लिए प्रशिक्षण का समर्थन करती है।
- आंध्र प्रदेश के लिए 28 डेटा और एआई लैब आवंटित किए गए हैं। 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रारंभिक वित्त पोषण जारी किया गया है, जबकि शेष प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 7 पॉलिटेक्निक संस्थानों की पहचान की गई है। स्वीकृत प्रयोगशालाओं में से एक सरकारी आईटीआई (गर्ल्स), विजयनगरम में स्थित है।

स्टार्टअप वित्तपोषण:

- सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एआई-सीओई) सीओई की स्थापना के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। एआई-सीओई स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, कृषि और रसद जैसे क्षेत्रों को कवर करता है, और कुशल प्रतिभा विकास का समर्थन करता है।
- अनुमोदित ढांचे के तहत, आंध्र प्रदेश में अमरावती और विशाखापत्तनम में दो (2) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एआई-सीओई) अनुमोदित किए गए हैं।

किफ़ायती गणना:

- कंप्यूट सर्विस प्रोवाइडर (सीएसपी) पैनल: 15, चार चरणों की पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें हाई-एंड और मिड-टियर दोनों प्रकार के जीपीयू शामिल हैं।
- सब्सिडी वाले कंप्यूट सपोर्ट के लिए स्वीकृत एंड-यूजर्स की संख्या: 237, सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स और एमएसएमई, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों, इंडियाएआई फेलो और छात्रों के लिए लगभग 93.18 लाख जीपीयू घंटे स्वीकृत किए गए हैं।
- इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल (https://compute.indiaai.gov.in) को संसाधनों की खोज, अनुरोध और अभिगम के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में संचालित किया गया है।
- एआई अनुसंधान, नवाचार, मॉडल विकास और नियोजन के समर्थन में इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल के माध्यम से आंध्र प्रदेश में पात्र स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संस्थाओं को एआई कंप्यूट अवसरंचना तक सब्सिडी वाली पहुंच प्रदान की जा रही है।

शासन में बदलाव के लिए इंडियाएआई चुनौती:

- आंध्र प्रदेश सरकार के रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (आरटीजीएस) के साथ साझेदारी में, इंडियाएआई मिशन ने इंडियाएआई चैलेंज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस लॉन्च किया है, जिसमें प्रमुख राज्य विभागों द्वारा पहचाने गए छह समस्या विवरणों को शामिल किया गया है।
- कुल 128 आवेदन प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में प्रयोगिक चरण के लिए उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार आंध्र प्रदेश के एआई इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण हितों से अवगत है, जिसमें विशाखापत्तनम में घोषित एआई हब भी शामिल है, जो एक निजी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है और इसे इंडियाएआई मिशन या किसी अन्य केंद्रीय योजना के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया गया है।

*****